भाजपा का रीट मामले में सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान बैरिकेट्स तोड़कर सिविल लाइंस फाटक पर जा रहे थे भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ता

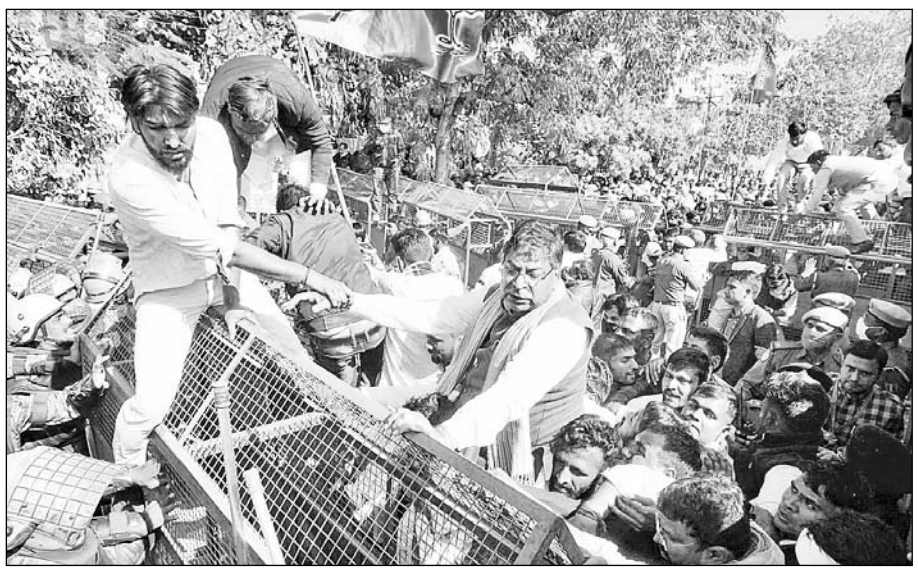

रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया के नेतृत्व में छात्र और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेट्स तोड़कर सिविल लाइंस फाटक जाने का प्रयास किया। लाठीचार्ज में घायल भाजपा कार्यकर्ता

- पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज
- मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए : पूनिया

जयपुर। रीट में हुई धांधली को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। रीट भर्ती परीक्षा मामले की सीबीआई जांच को लेकर भाजयुमो ने मंगलवार को सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। भाजपा मुख्यालय से सिविल लाइन कूच कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो हंगामा खड़ा हो गया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं के चोटें आई हैं। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार से उन्हें रोकने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओ के साथ सिविल लाइन्स फाटक पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और उन्हें लेकर झोटवाड़ा थाने पहुंची, जहां पूनिया सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस प्रकरण में भले ही एसओजी ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया हो। जो लोग इस प्रकरण से जुड़े हुए हैं इसमें बड़े नेता भी शामिल हैं। जिन्हें सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सीबीआई की जांच होने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।

भाजयुमो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सिविल लाइन फाटक पर जाने के लिए लगाए गए बैरीकेट्स को गिराकर कार्यकर्ता सिविल लाइन फाटक की तरफ जाने लगे। पुलिस ने उन्हें आइनोक्स की तरफ से जाने के लिए कहा, लेकिन कई कार्यकर्ता बैरीकेट्स के उपर चढ़ गए और बैरीकेट्स को हटाने लगे। इस पुलिस ने कार्यकताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के चलते कार्यकर्ताओं ने बैरीकेट्स हटाने शुरु किए इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरु कर दिया। इससे कई कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों को भी चोट आई हैं।

जयपुर शहर अध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी का कहना है कि भाजपा प्रदेश कार्यालय से रवाना हुए थे। शांति के साथ सभी महिला खड़ी थी। भाईयों को लाठी मारना शुरु कर दिया। जब हम आए तो यहां चार घोड़े पर पुलिस वाले बैठे हुए थे। ये लोग आए और भाईयों के साथ मारपीट के बाद कार्यकर्ता आरती के हाथ पर डंडा मार दिया। फिर मेरे गर्दन पर डंडा मार दिया। अनुराधा का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी साथ में नहीं थी। गहलोत के राज में गूंगी बहरी महिला सुरक्षित नहीं तो फिर हमारी बिसात क्या है। हम बेरोजगारी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने हमारे साथ मारपीट की। जो महिला कार्यकताएं घायल हुई उनमें वृत्तिका, वंशिका, परनामी है। वहीं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष आरती सिंह ने बताया कि हम बेरोजगारी के लिए शांति पूर्वक अपनी मांग के लिए आए थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को चाहिए था कि वह उनकी बात शांतिपूर्वक सुनते। लेकिन उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज के आदेश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में महिलाओं के साथ इस तरह मारपीट करना शोभा नहीं देता। वह उनकी बात सुनते और शांतिपूर्वक समाधान निकालते। इस दौरान पुलिस के साथ भाजयुमो कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की से कई पुलिसकर्मियों की वर्दी फट गई तो कई लोगों के हाथ में चोट तो किसी के पैर में चोट आई हैं। किसी के सिर में तो किसी के पीठ में चोट लग गई। वही शाम को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, घनश्याम तिवाड़ी घायल कार्यकर्ताओं से मिलने एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर पहुंच कर मुलाकात की।

हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर राज्यपाल ने रोक लगाई

जयपुर। कुलाधिपति व राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। यह कदम नियमों, मापदंडों व योग्यता की अनिवार्य शर्तों को लांघकर अपनाई जा रही भर्ती प्रक्रिया पर पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा जताई गई आपत्ति और अखबारों में छपी खबरों पर संज्ञान लेते हुए उठाया गया है।

देवनानी ने राज्यपाल को 21 जनवरी को लिखे पत्र में विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी द्वारा मनमाने तरीके से भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिए जाने का विस्तार से खुलासा किया था। इस पर जयपुर में विभिन्न अखबारों में खबरें भी छपी थीं। राज्यपाल मिश्र ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सबीर कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। देवनानी ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा था कि नियमानुसार कोई भी पद विज्ञापित करने से पूर्व उस पर लागू होने वाले आरक्षण और रोस्टर के आलोक में परीक्षण करना आवश्यक होता है। उन पर प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित करने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाता है। विभिन्न शैक्षिणक पदों पर विज्ञापन से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर रोस्टर कैलेण्डर चस्पा कर उन पर आपत्तियां मांगी गई। अन्य लोगों के साथ विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने भी आरक्षण प्रावधानों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी और कमी आई

राज्य में मंगलवार को 6212 नए संक्रमित मिले, जबकि सोमवार को 6369 रोगी सामने आए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में मंगलवार को भी करोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी और कमी आई है। इस दौरान राज्य में 6212 नए संक्रमित मिले हैं। जबकि 10 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इस बीच प्रदेश में करोना से 20 और लोगों की मौत हुई है।

- जयपुर में भी थोड़ी गिरावट के बाद 1230 नए संक्रमित मिले हैं।
- प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 10 हजार से ज्यादा मरीज ठीक होने के साथ ही एक्टिव केस घटकर 63036 रह गए हैं।
- राज्य में मंगलवार को करोना से 20 और लोगों की मौत हो गई है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 157 और मामले कम आने के साथ ही 6212 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 6369 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में भी नए संक्रमितों की संख्या में और गिरावट आई है। मंगलवार को जिले में 1230 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 633, उदयपुर में 495, अलवर में 410, चित्तौड़गढ़ में 396, कोटा में 320, भरतपुर में 248, गंगानगर में 233, भीलवाड़ा में 192, हनुमानगढ़ में 178, अजमेर में 168, सीकर में 158, टोंक में 132, प्रतापगढ़ में 127, राजसमंद में 123, चूरू में 117, सवाई माधोपुर में 109 और झालावाड़ में 102, बीकानेर में 95, जैसलमेर व नागौर में 94-94, बाड़मेर में 89, डूंगरपुर में 87, बूंदी में 82, धौलपुर में 77, बारां में 49, बांसवाड़ा में 44, झुंझुनूं में 40, दौसा में 39, सिरोही में 27, पाली में 11, जालौर में 10 और करौली में 3 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 12 लाख 12 हजार 633 संक्रमित सामने आ चुके हैं। इनमें से 11 लाख 40 हजार 309 लोग स्वस्थ भी हो चुके है। राज्य में फिलहाल रिकवरी रेट फिर बढ़कर 94.03 फीसदी पर पहुंच गई है। वहीं संक्रमण दर 10.78 प्रतिशत दर्ज की गई है। इधर राज्य में मंगलवार को भी 10 हजार 173 संक्रमित ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 63 हजार 36 रहे गए हैं। राजधानी जयपुर में भी इनकी संख्या घटकर 15 हजार 549 पर आ गई है। उधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 20 और मरीजों की मौत हो गई है। इनमें जयपुर में 4, करौली, नागौर, पाली, सीकर और उदयपुर में 2-2, टोंक, सिरोही, झुंझुनूं, दौसा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में 1-1 मरीज की मौत हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9288 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

राजधानी में मंगलवार को 93 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 75 नए मरीज झोटवाड़ा इलाके में मिले है। इसके अलावा आमेर में 49, फागी में 56, गोविन्दगढ़ में 61 नए संक्रमित मिले हैं। शेष स्थानों पर इससे कम मरीज सामने आए। वहीं आज भी 41 मरीज ऐसे रहे जिन्हें अज्ञात की श्रेणी में रखा गया है। जिले में इस बीच 2416 मरीज रिकवर हुए हैं।

सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कर्मचारी महत्वपूर्ण कड़ी : मुख्यमंत्री

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार राज्य कर्मचारियों के हित में सदैव तत्पर रही है। अधिकारी-कर्मचारी राज्य सरकार का अभिन्न अंग हैं और वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के निचले स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न कर्मचारी महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट को समावेशी एवं लोक कल्याणकारी स्वरूप देने की दिशा में राज्य सरकार सभी वर्गों के सुझाव ले रही है। इसी क्रम में कर्मचारी महासंघों को भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है। इन सुझावों के आधार पर सरकार को कर्मचारी वर्ग के हित में फैसले लेने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार ने को अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न कर्मचारी महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित किया।

इधर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारे लाल चौधरी ने मुख्यमंत्री के समक्ष नर्सेज की महत्वपूर्ण मांगों को बजट में शामिल करने की मांग रखी। प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष से संवाद के दौरान नर्सेज संवर्ग की प्रमुख मांगे मैंस भत्ता 1200 से बढ़ाकर 2250 करने, महिला नर्सिंग कर्मियों के छोटे बच्चों के लिए अस्पताल में क्रैच खोलने, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने, नर्सिंग पदनाम का शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करने, नए नर्सिंग महाविद्यालय में पदों का सृजन करने, करोना काल की प्रोत्साहन राशि को शीघ्र दिलाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत नर्सेज को दवाई लिखने का अधिकार देने और ग्रामीण भत्ता दिलाने, नर्सेज स्टूडेंट का स्टाइ फंड बढ़ाने, नर्सिंग संवर्ग की समयबद्ध पदोन्नित की बजट में घोषणा की जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने नर्सेज पदाधिकारियों को नर्सेज की प्रशंसा करते हुए उनकी मांगों को बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया।

'नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए सदन में भी सरकार को घेरेंगे'

जयपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि हम नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रीट के अभ्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वह सोशल मीडिया से बाहर आए और युवा मोर्चा के आंदोलन को सड़कों पर समर्थन दें। भाजपा सड़क पर और कानूनी कार्यवाही लड़ने के लिए तैयार है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, तब तक हम इस निकम्मी सरकार को सदन में भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे।

उन्होंने कहा कि 16 लोग शामिल हुए थे। 16 हजार भी सड़कों पर आ गए तो मेरा दावा है कि यह सरकार गिर जाएगी और रीट का न्याय भी हो जाएगा। इस आंदोलन को लेकर हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, हमने सभी नौजवानों को साथ लेकर इस आंदोलन का आगाज किया है, ना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का अभिमान है। जो नौजवानों को न्याय दिला सके हम नैतिक रुप से उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के दृश्य मैने कभी नहीं देखे और मेरे से पहले के लोग भी यही कहते हैं कि इस तरह की धांधली उन्होंने भी पहले कभी नहीं देखी। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की राजस्थान में आखिरी लड़ाई लड़ रही है। उन्हें लगता है कि दुबारा सरकार नहीं आएगी जितना लूट सकते हो लूट लो। जितने कांग्रेस के लोगों को भर्ती कर सकते हो भर्ती कर लो। मेरा इस खुले मंच से ऐलान है उनको चुनौती है। मुझे डर है कि अगर सही तरीके से जांच नहीं होती है, सरकार संरक्षण देती है तो लाखों विद्यार्थियों को नौकरी से वंचित होना पड़ सकता है।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य की गहलोत सरकार को तानाशाह करार दिया है। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया की गिरफ्तारी पर शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार ने एक बार फिर जनता की आवाज दबाने की तानाशाही दिखाई है। रीट परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच राजस्थान के हर जागरूक नागरिक की मांग है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉ. सतीश पूनिया इसके लिए ही शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करवाकर गहलोत जी ने साबित किया कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है।

एलआईसी के जीवन अक्षय और न्यू जीवन शांति योजना में संशोधन

जयपुर, (का.सं.)। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 फरवरी से अपनी वार्षिकी योजनाओं के संबंध में एलआईसी की जीवन अक्षय और एलआईसी की नई जीवन शांति की वार्षिकी दरों को संशोधित किया है। संशोधित वार्षिकी दरों के साथ इन योजनाओं का संशोधित संस्करण विक्रय के लिये 1 फरवरी से उपलब्ध होगा।

मोदी सरकार के बजट से सभी वर्ग आत्मनिर्भर बनेंगे : डॉ. पूनिया

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने केन्द्र की मोदी सरकार के लोक कल्याणकारी बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार का बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं सहित सभी वर्गों के लोक कल्याण एवं उत्थान को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, जिससे हर वर्ग स्वाभिमान के साथ आर्थिक उन्नति के साथ आत्मनिर्भर बनेगा। डॉ. पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की पांच बड़ी नदियों को जोड़ने का बड़ा ऐलान किया है, जिससे देश के किसान भाईयों की 9 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा एवं नाबार्ड के जरिए कृषि स्टार्टअप योजना को बढ़ावा मिलेगा, जो कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय साबित होगा। हर वर्ष 25 हजार किलोमीटर सडक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। टीवी के माध्यम बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया है। छोटे एवं मध्यम उद्योगों को 2 लाख करोड़ के ऋण का प्रावधान किया तथा ऑनलाइन माध्यम से एक राष्ट्र, एक रजिस्ट्री का भी निर्णय लिया गया है। बजट से देश के विकास को बुनियादी तौर पर नई दिशा मिलेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल होगी। राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समावेशी विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुन्धरा राजे ने कहा है कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को साकार करने और आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला है।

बजट घोर निराशाजनक: डॉ. कल्ला

जयपुर, (का.सं.)। शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट सभी वर्गों के लिए घोर निराशाजनक है। डॉ. कल्ला ने कहा कि करोना के कारण विषम परिस्थितियों से गुजर रही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात हो या बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा एवं महंगाई से त्रस्त आमजन, गरीब, किसान व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हो या फिर श्रमिक वर्ग, सभी लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानो की आय दुगनी करने का वादा किया था। जब ये सरकार पहली बार आई तो युवाओं को हर साल दो करोड़ रोजगार देने के सपने दिखाए गए थे। जनता से किए ऐसे कई वादों की कसौटी पर लगातार नाकामयाब रही केंद्र सरकार के इस बजट में एक बार फिर सभी लोगो की उम्मीदों को ठेंगा दिखाते हुए महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने वाला घाटे का बजट पेश किया गया है जो मात्र कॉरपोरेट घरानों की आय में इज़ाफा करने वाला साबित होगा।

जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर रही सौम्या गुर्जर के निलंबन पर रोक

अदालत ने मामले की जांच पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए भी राज्य सरकार को आदेश दिया

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम जयपुर की मेयर रही सौम्या गुर्जर के निलंबन आदेश पर मामले में न्यायिक जांच कार्रवाई का नतीजा आने तक अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की जांच पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत में पेश करने के लिए कहा है। जस्टिस संजय किशन कौल व एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए।

डॉ. सौम्या गुर्जर

- सौम्या ने एसएलपी में कहा कि नगर निगम कमिश्नर द्वारा मामले में दर्ज कराई एफआईआर में ऐसा कोई गंभीर आधार नहीं है जिस पर राज्य सरकार प्रार्थिया को मेयर पद से निलंबित किया जाता।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के 16 जुलाई 2021 के आदेशानुसार प्रार्थिया पर मेयर के तौर पर अनुचित भाषा का उपयोग करने का आरोप है। जबकि अन्य पार्षदों पर अधिकारी के साथ हाथापाई व धक्का-मुक्की करने का आरोप है। वहीं प्रार्थिया के मामले में राज्य सरकार की न्यायिक जांच की साक्ष्य प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में न्यायिक जांच कार्रवाई का नतीजा आने तक प्रार्थिया की हद तक उसके निलंबन के आदेश पर रोक लगाया जाना उचित होगा। सुनवाई के दौरान प्रार्थिया की ओर से कहा कि राज्य सरकार ने उसके मामले में न्यायिक साक्ष्य जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली है। राज्य सरकार अब दूसरे अन्य के मामलों में आठ गवाहों के बयान दर्ज करवाना चाहती है और इन दोनों मामलों को एक साथ संलग्न कर अंतिम बहस करवाना चाहती है। इस पर अदालत ने कहा कि वे मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रार्थिया की भूमिका को देखते हुए न्यायिक जांच कार्रवाई का नतीजा आने तक उनके निलंबन आदेश पर रोक लगाई जा रही है। सौम्या गुर्जर ने एसएलपी में हाईकोर्ट के 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

सौम्या ने एसएलपी में कहा कि नगर निगम कमिश्नर द्वारा मामले में दर्ज कराई एफआईआर में ऐसा कोई गंभीर आधार नहीं है जिस पर राज्य सरकार प्रार्थिया को मेयर पद से निलंबित किया जाता। वहीं नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 (1) (डी) की संवैधानिकता वैधता को भी चुनौती देते हुए कहा कि मेयर पद से उनका निलंबन गलत किया है, इसलिए उनके निलंबन पर रोक लगाई जाए।

सौम्या पुनः कुर्सी पर कब बैठेंगी, फिलहाल तय नहीं

- चर्चा है कि अदालत के आदेश की कॉपी मिलने के बाद राज्य सरकार रिव्यू करेगी, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सौम्या गुर्जर के पुनः मेयर पद पर बहाल होने की राह खुल गई है। हालांकि वे दुबारा मेयर की कुर्सी पर कब बैठेगी, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद सरकार की ओर से रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

मामले में भाजपा की ओर से पूरे मामले की निगरानी कर रहे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अनैतिक व असंवैधानिक निर्णय को गलत मानते हुए यह स्टे दिया है। यह लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। सौम्या गुर्जर ने कहा कि सत्य सिर्फ परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। गहलोत सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से मेयर पद से हटाया था, सुप्रीम कोर्ट में सत्य की जीत हुई है। ज्ञात रहे कि गहलोत सरकार ने गत 6 जून को सौम्या गुर्जर को मेयर पद से और अन्य तीन पार्षदों को आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ हुए विवाद के बाद निलंबित कर दिया था। इस निलंबन के बाद राज्य सरकार ने इस प्रकरण की न्यायिक जांच भी शुरू करवा दी थी। सरकार के निलंबन के फैसले को सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने प्रकरण में न्यायिक जांच होने तक दखल देने और निलंबन के आदेशों पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सौम्या गुर्जर के समर्थन में भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहले 4 बार सुनवाई हो गई, लेकिन अब तक कोई निणर्य नहीं हुआ था। वहीं दूसरी ओर 31 जनवरी को ही राज्य सरकार ने ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर शील धाभाई के कार्यकाल को अगले 60 दिन के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने शील धाभाई का कार्यकाल चौथी बार बढ़ाया है। इससे पहले सरकार ने दिसंबर में आदेश जारी करके हुए 60 दिन के लिए कार्यकाल बढ़ाया था।

आम बजट आम आदमी के लिए निराशाजनक : पायलट

जयपुर, (का.प्र.)। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद में प्रस्तुत आम बजट आम आदमी के लिए पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि "महंगाई सहित-रोजगार रहित" इस बजट और जीडीपी से देश का युवा हताश और निराश हुआ है क्योंकि जीडीपी का अधिकतर हिस्सा पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गरीबों, युवाओं और बेरोजगारों के लिए बजट में एक शब्द भी नहीं बोला गया। आजादी के अमृतकाल के नाम से 25 वर्षों का विजन पेश किया गया है, जबकि इस कार्यकाल के 3 वर्षों सहित पिछले 7 सालों की घोषणाओं का कोई हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने पर 5 वर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और अब 25 वर्षों का विजन दे रही है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी की घोषणा नहीं होने से किसानों में भारी निराशा है और यह 700 किसानों के बलिदान का अपमान है।

कृषि के लिए बजट में कोई ठोस घोषणा नहीं है। पिछले साल एमएसपी खरीद पर 2.42 लाख करोड़ खर्च हुए जबकि इस साल 2.37 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पायलट ने कहा कि चीन से खतरे को देखते हुए, रक्षा खर्च में कमी करना और 2014 की तुलना में इसका जीडीपी के 2.6 प्रतिशत से घटकर 2.2 प्रतिशत रह जाना बहुत ही चिंताजनक है। सवा लाख पदों को खाली रखकर सरकार देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है।

उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करने वाली सरकार ने बजट भाषण में 15 लाख नौकरी देने की सूचना दी है और अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरी का वादा किया है। सरकार की युवाओं और बेरोजगारों के साथ इससे बड़ी वादाखिलाफी हो नहीं सकती। वित्तीय घाटे के 6.8 प्रतिशत तक पहुंच जाना यह प्रमाणित करता है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत कठिन दौर से गुजर रही है और रिजर्व बैंक से लगातार नकदी छापकर काम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च 2014 में देश पर कर्ज 53 लाख करोड़ था जो अब 136 लाख करोड़ हो चुका है, भाजपा सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है।